

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे

सदस्य

निगरानी प्र० क० 2494 / 11/2012 विरुद्ध आदेश दिनांक 18 7 2012

- पारित- द्वारा - तहसीलदार हुजूर जिला रीवा - प्र०क० 390/अ 6/10 11

डा० सुरेन्द्र सिंह पुत्र स्व. निर्भयसिंह  
मोहल्ला उपरहटी रीवा तहसील हुजूर  
जिला रीवा, मध्य प्रदेश

---आवेदक

विरुद्ध

- 1 वृजंगद्र सिंह पुत्र स्व. निर्भयसिंह
  - 2 देवेन्द्र सिंह पुत्र स्व. निर्भयसिंह
  - 3- लोकेन्द्र सिंह पुत्र स्व. निर्भयसिंह
- तीनों निवासी मोहल्ला उपरहटी रीवा  
तहसील हुजूर जिला रीवा, मध्यप्रदेश

अनावेदकगण

आवेदक के अभिभाषक श्री विनय कुमार  
अनावेदक के अभिभाषक श्री भूपेन्द्रसिंह धाकड़

आदेश

(आज दिनांक 12 6 - 2014 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार हुजूर जिला रीवा द्वारा प्र०क० 390/अ-6/  
10-11 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 18-7-12 के विरुद्ध म०प्र०भू राजस्व  
संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

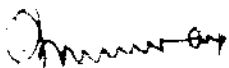
2/ प्रकरण का सारोश यह है अनावेदकगण ने तहसीलदार हुजूर जिला  
रीवा के समक्ष म०प्र०भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 109, 110 के अंतर्गत  
आवेदन पत्र प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम कुटुलिया स्थित भूमि कुल कित्ता 8  
कुल रकबा 12.81 ए उनके स्वर्गीय पिता निर्भयसिंह के नाम थी, जिनका  
देहान्त दिनांक 15 10 10 को हो चुका है उन्होंने अपने जीवनकाल में बरीयत  
दिनांक 24.6.2004 लिखी थी, जिसके अनुसार तीनों भाईयों को हिरसा 1/3

समानुपातिक दिया है इसलिये नामांत्रण किया जावे। तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 390/अ-6/ 10-11 पंजीबद्ध किया एवं सुनवाई प्रारंभ की। सुनवाई के दौरान आवेदक ने इस आशय की आपत्ति दिनांक 29.6.12 को प्रस्तुत की, कि वादित संपत्ति के संबंध में पंचम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 रीवा के न्यायालय में स्वत्व वाद कमांक 138 ए / 11 प्रचलित है जिसमें बसीयत निष्प्रभावी घोषित होना है इसलिये व्यवहार न्यायालय के आदेश के निराकरण तक राजस्व न्यायालय की कार्यवाही रोकी जावे। तहसीलदार हजूर ने अंतरिम आदेश दिनांक 18-7-12 पारित किया एवं आवेदक की आपत्ति खारिज कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी है।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत लेखी बहस पर विचार किया तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस के तथ्यों एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर वस्तुस्थिति यह है कि सुनवाई के दौरान दिनांक 24-8-11 को आवेदक ने इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की कि बसीयत कूटरचित है एवं मृतक निर्भयसिंह के चार पुत्र हैं जिनमें आपत्तिकर्ता भी पुत्र हैं इसलिये उसे पक्षकार बनाया जाकर सुनवाई की जावे। इसी प्रकार आवेदक द्वारा दिनांक 29.6.12 को तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग रखी कि सिविल न्यायालय रीवा में व्यवहार वाद कमांक 138 ए/2011 मान पंचम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के यहां कूटरचित बसीयतनामा को शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित करने हेतु दावा प्रचलित है, इस वाद के निराकरण तक तहसील न्यायालय की कार्यवाही स्थगित रखी जावे। इस आवेदन पर तहसीलदार ने अंतरिम आदेश दिनांक 18-7-12 से आपत्ति खारिज की एवं प्रकरण साक्ष्य हेतु लगा दिया।

6/ विचार योग्य बिन्दु यह है कि जिस बसीयत के आधार पर अनावेदकगण ने वादग्रस्त भूमि पर नामान्तरण की मांग की है और उसी बसीयत को

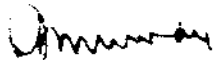


कूटरचित होना बताते हुये – बसीयत को शून्य घोषित कराये जाने हेतु व्यवहार न्यायालय में प्रचलित प्रकरण के निराकरण तक राजस्व न्यायालय की कार्यवाही रोक देना चाहिये अथवा नहीं ? तहसील न्यायालय में मामला बसीयत के आधार पर नामांतरण का है और बसीयत कूटरचित होने के आधार पर व्यवहार वाद प्रस्तुत कर बसीयत शून्य घोषित करने का मामला क्रमांक 138 ए/2011 मान. पंचम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 रीवा के न्यायालय में विचारित है जिसमें दिनांक 23-12-11 को आदेश पारित किया है कि “ प्रतिवादीगण को आदेश दिया जाता है कि आगामी तिथि तक वादग्रस्त संपत्ति की स्थिति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन व विक्रय नहीं करेगा।” इस प्रकरण में सरल क्रमांक 4 पर मध्य प्रदेश शासन प्रतिवादी है और यह आदेश राजस्व विभाग पर भी बंधनकारी है यानि की मृतक निर्भय सिंह द्वारा छोड़ी गई वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार का फेरफार अनावेदकगण एवं म०प्र०शासन नहीं करेगा।

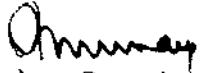
7/ बसीयत के संबंध में व्यवहार न्यायालय में बसीयत सही है अथवा गलत है – निर्णय नहीं हो जाता -- बसीयत के आधार पर नामान्तरण की कार्यवाही कर वादग्रस्त भूमि के भू अभिलेख में अथवा भूमि के स्वत्वांतरण में राजस्व न्यायालय को विचार नहीं करना चाहिये, क्योंकि व्यवहार वाद में सरल क्रमांक-4 पर मध्य प्रदेश शासन पक्षकार है।

(अ) भू राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.) धारा 109, 110 एवं उत्तराधिकार अधिनियम 1925 – धारा 63 (ग) -- व्यवहार न्यायालय में बसीयत का सिद्धीकरण, असिद्धीकरण लम्बित- विल सावित हो जाने पर ही नामान्तरण पर विचार किया जा सकेगा।

(ब) साक्ष्य अधिनियम की धारा -68 -- विहित रीति में विल सावित किये बिना विल सावित होना नहीं मानी जावेगी।



- (स) भू राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.) धारा 109, 110 - व्यवहार न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालय पर बन्धनकारी हैं। बसीयत की संदिग्धता के संबंध में व्यवहार वाद प्रचलित - ऐसी बसीयत के आधार पर राजस्व न्यायालय नामान्तरण कार्यवाही नहीं कर सकता।
- 7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार हुजूर द्वारा प्र०क्र० 390/अ-6/ 10-11 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 18-7-12 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि मान. पंचम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 सीवा के न्यायालय में प्रचलित व्यवहार वाद क्रमांक 138 ए/11 में अंतिम निर्णय होने के पश्चात् तदनुसार संहिता की धारा 109, 110 के अंतर्गत कार्यवाही विचारित की जावे।

  
(अशोक शिवहरे)  
सदस्य  
राजस्व मंडल  
मध्य प्रदेश ग्वालियर